an>

Title: Need to accord sanction to the proposal of Government of Gujarat for setting up Anganwadi Centres in the State.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ः आंगनबाड़ी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक अहम परियोजना है। इसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत और राज्य सरकार का 25 प्रतिशत हिस्सा होता है।

गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को योजना-2, आईसीडीएस को 2013-14 में 198 आंगनबाड़ी तथा 19 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल मिलाकर 217 की परमीशन के लिए दरखास्त की गई थी। इस प्रकार की दरखास्त वर्ष 2014-15 में गुजरात सरकार द्वारा 792 आंगनबाड़ी तथा 728 मिनी आंगनबाड़ी कुल मिलाकर 1520 की दरखास्त की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में 2015 तक कुल मिलाकर 990 आंगनबाड़ी तथा 747 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों कुल 1737 आंगनबाड़ी केन्द्रों की दरखास्त की थी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 677 आंगनबाड़ी तथा 215 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मंजूरी मिल गई है, बाकी बची हुई 313 आंगनबाड़ी तथा 532 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मंजूरी की दरखास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

मेरी मांग है कि दूर दराज इलाकों में तथा नगर इकाई की गरीब बस्तियों में रहने वाले शिशुओं के विकास की टूटती कड़ियों को जोड़ा जा सके और शिशुओं की जिंदगी को संवार सकें, इसलिए जल्द से जल्द बाकी केन्द्रों की मंजूरी दी जाए।